परिवर्तन ◆ मध्यवर्ग या इसमें शामिल होने की चाह रखने वाले राजनीतिक आयाम को बदल रहे हैं

बढ़ रही हैं मध्यवर्ग की राजनीतिक ख्वाहिशें

पिछले दिनों जब जनलोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन चरम पर था तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचता रहा। मैं इस सरगर्म माहौल के ठंडा पड़ने का इंतजार कर रहा था । अन्ना के अनशन के दौरान कई लोगों ने इसे मध्यवर्ग का आंदोलन करार दिया था। लेकिन मेरा मानना है कि इस पूरे आंदोलन को मध्यवर्ग का आंदोलन ठीक नहीं होगा। पहली बात तो यह है मध्यवर्ग के लिए दुनिया में भर में कोई स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। इस शब्द को आम विमर्श में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है और इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। अन्ना के आंदोलन में लोगों को जो हुजूम उमड़ा उस पर सरसरी तौर पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि इसमें इस समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल थे। भारी बारिश की परवाह किए बिना इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे बच्चों में पब्लिक और सरकारी स्कूल दोनों में पढ़ने वाले शामिल थे।

आंदोलन में नौकरी करने वाले, बेरोजगार, आंशिक रोजगार में लगे युवा, पेशेवर, छोटे कारोबारी, दुकानदार, गृहिणी और रिटायर्ड लोग शामिल थे। इस तरह अन्ना को समर्थन का एक बड़ा आधार मिल गया।

मेरा मानना है कि इस आंदोलन का चरित्र चित्रण करने की जल्दबाजी में हमने एक खास वर्ग को भूला दिया या फिर अपनी सुविधा के लिए इसे मध्यवर्ग में शामिल कर लिया। यह वह वर्ग है जो वंचितों और मध्य वर्ग के बीच खड़ा है। इसे मैं अक्सर आकांक्षी का नाम देता हूं। यह वर्ग मध्यवर्ग में शामिल होना चाहता है। इस वर्ग में शामिल परिवारों की औसत आय डेढ़ लाख रुपये से लेकर 3,40,000 रुपये तक होती है (2009-2010 की कीमतों पर)। इस परिवार में कमाने वाला मुख्य व्यक्ति पर्याप्त तौर पर शिक्षित नहीं होता है इसलिए वह कम वेतन वाला क्लर्की या इस श्रेणी के काम करता है। लेकिन वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं ताकि वे मध्यवर्ग में शामिल हो सकें।

मध्यवर्ग में शामिल होने की इच्छा रखने वाला यह समूह ही भारत की बहुप्रचारित विकास गाथा का हिस्सा होना चाहता है और इसमें शिक्षा एक अहम भूमिका निभाने वाला माध्यम बन कर उभरी है। मध्यवर्ग में शामिल होने की यही आकांक्षा उन्हें इस आंदोलन में शामिल होने को प्रेरित कर रही थी।

लेखक एनसीएईआर में मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च के डायरेक्टर हैं।भारतीय समाज में आ रहे एक अहम बदलाव पर उनका यह लेख।

राजेश शुक्ला

भ्रष्टाचार के खिलाफ यह संघर्ष सिस्टम के खिलाफ उनके बड़े आंदोलन का एक हिस्सा है, जो गैर बराबरी पैदा कर रहा है। यह सिस्टम उन्हें एक वाजिब और अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के मौके हासिल करने से रोक रहा है। इन चीजों से महरूम रहना ही उन्हें तरक्की नहीं करने दे रहा है।

वर्ष 2015-16 तक इस वर्ग में शामिल लोगों की तादाद बढ़ कर 44.40 करोड़ हो जाएगी (आबादी का 34 फीसदी) । जबकि मध्यवर्ग के लोगों की तादाद बढ़ कर 26.70 करोड़ हो जाएगी। इस तरह संख्या बल में इन लोगों की तादाद मध्यवर्ग से ज्यादा हो जाएगी। इस दशक के मध्य तक इस दोनों वर्ग के लोग पूरी आबादी का 54 फीसदी हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि गरीब सबसे बड़ा या प्रभावी वर्ग नहीं रह जाएगा, जिसे खुश करने के लिए नेताओं को मशक्कत करनी पड़ेगी। आर्थिक मुद्दे अब चुनाव के नतीजे तय करने लगे हैं। अहम मुद्दा वर्गों के बीच बंटवारे का नहीं बल्कि यह है कि आय के वितरण में सामाजिक उभारों का असर दिख रहा है (एलेसिना, ग्लेसर, 2004, सेल्वे 2011)। इसलिए मेरी राय में इस दोनों वर्गों की राजनीतिक चेतना के उभार का असर 2014 और 2019 के चुनावों में जरूर दिखेगा।

लेकिन यह कहानी का एक हिस्सा है। अब हम जो एक के बाद एक जो घटनाएं देख रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि भविष्य में ये न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगी बल्कि काफी हद तक हमारे लोकतंत्र और राजनीति को भी एक नया शक्ल दे देंगी।

दरअसल इस समय जो राजनीतिक चेतना दिख रही है, उससे जनसांख्यिकी पहलू का बड़ा हाथ है। वर्ष 2009 में भारत में 13 से 35 साल की उम्र के 45.90 करोड़ लोग थे। अगले चुनावों मे होने वाले मतदान में इस समूह की बड़ी भूमिका होगी।

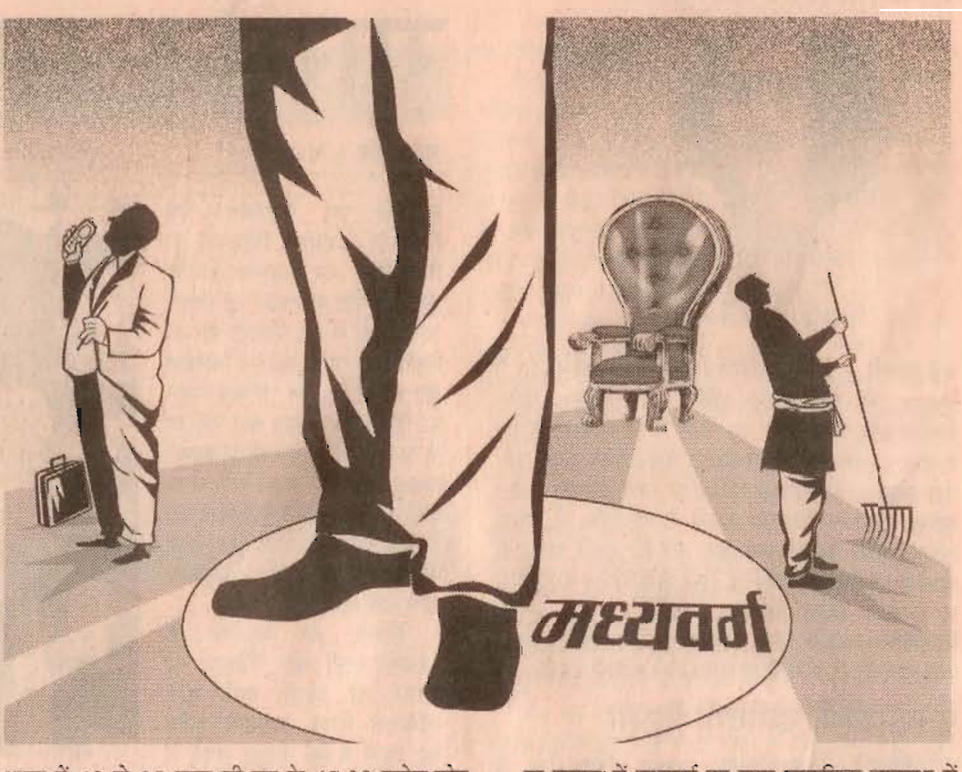

उदारीकरण के दौर में बड़ी और शिक्षित होने वाली यह पीढ़ी समान अवसर और योग्यता के सिद्धांत में विश्वास करती है। सिस्टम में भ्रष्टाचार और संसाधनों के लगातार कुछ हाथों तक सिमट जाने के इस दौर में उसे लग रहा है कि समावेशी विकास का नारा कितना खोखला या उनके सामने किस तरह की दिक्कतें खड़ी हैं। इसलिए अन्ना का आंदोलन सिस्टम को साफ-सुथरा करने की हमारी इच्छा को व्यक्त करने वाला है।साथ ही यह भी कि समतावादी समाज कैसे बनाया जाए।

हर समाज में मध्यवर्ग का उदय सामाजिक व्यवस्था में बदलाव से जुड़ा रहा है।जैसे-जैसे इसकी तादाद बढ़ती है यह यथास्थितिवाद को चुनौती देते हुए सत्ता की ताकतों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है।सत्ता और नीति-निर्माण में उन्हें अपना वाजिब हक चाहिए होता है और राजनीतिक भद्रलोक को चुनौती देता है।भले ही अन्ना के आंदोलन को भ्रष्टाचार के खिलाफजनउभार कहा जा रहा हो लेकिन इसे मिले समर्थन से जाहिर होता है देश में राजनीतिक आयाम बदल रहे हैं। अब यह एक ऐसी जगह पहुंच गया है, जहां लोग विकास के मुद्दे और सार्वजनिक तौर पर जिम्मेदारी लेने का सवाल उठाने लगे हैं।